

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता और दोहरा कराधान बचाव समझौता

प्रलिस के लिये:

[केंद्रीय परत्यक्ष कर बोर्ड](#), [अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते](#), [दोहरा कराधान अपवंचन समझौता](#), [कर चोरी](#)

मेन्स के लिये:

कर नश्चितता सुनश्चिति करने में APAs का महत्त्व, दोहरा कराधान बचाव समझौते और उनका महत्त्व, व्यवसाय करने में आसानी

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

[केंद्रीय परत्यक्ष कर बोर्ड](#) (Central Board of Direct Taxes - CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 125 [अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों](#) (Advance Pricing Agreements - APAs) पर हस्ताक्षर करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

- APA हस्ताक्षरों में यह उछाल स्थानांतरण मूल्य निर्धारण नियमों के बढ़ते महत्त्व और करदाताओं को नश्चितता प्रदान करने के प्रयासों को रेखांकित करता है।
- एक अतिरिक्त विकास में भारत और मॉरीशस ने कर चोरी पर अंकुश लगाने और नषिपक्ष कराधान प्रथाओं को सुनश्चिति करने के लिये अपने [दोहरे कराधान अपवंचन समझौते](#) (Double Taxation Avoidance Agreement - DTAA) में संशोधन किया है।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता क्या है?

- **परचिय:**
 - APA करदाता और कर प्राधिकरण के बीच स्थानांतरण कीमतों पर एक औपचारिक व्यवस्था है।
 - APA व्यवसायों को कर अधिकारियों द्वारा उनके लेन-देन की कीमतों को चुनौती दिये जाने के जोखिम को कम करने की अनुमत देता है।
 - APA कार्यक्रम का व्यापार करने में सुलभता ([ईज ऑफ डूइंग बिजनेस](#)) को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मशिन में महत्त्वपूर्ण योगदान है, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs) के लिये जिनके समूह संस्थाओं के भीतर बड़ी संख्या में सीमा पार लेनदेन होते हैं।
- **APAs के प्रकार:**
 - **एकपक्षीय APA:**
 - घरेलू संस्थाओं के बीच लेन-देन के लिये जोखिम सीमिति करना।
 - वदिशी संस्थाओं के साथ लेन-देन पर दोहरे कराधान से बचने की कोई गारंटी नहीं। अन्य APA प्रकारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम कार्यवाही।
 - **द्विपक्षीय APA:**
 - घरेलू इकाई और वदिशी इकाई के बीच लेन-देन के लिये जोखिम सीमिति करना। **दोहरे कराधान के जोखिम** को समाप्त करना। लंबी कार्यवाही के लिये दोनों राज्यों को सहमत होना होगा।
 - **बहुपक्षीय APA (MAPA):**
 - वे 3 या अधिक राज्यों में संबंधित संस्थाओं के बीच लेन-देन के जोखिम को कम करते हैं, जटिल लेन-देन के लिये एक सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं और दोनों पक्षों के लिये सुरक्षा सुनश्चिति करते हैं, हालांकि कार्यवाही में अधिक समय लगता है।
- **APA की प्रमुख विशेषताएँ:**
 - APA प्रक्रिया **स्वैच्छक** है और **स्थानांतरण मूल्य निर्धारण विवादों को हल करने** के लिये अपील और अन्य [दोहरे कराधान अपवंचन समझौते](#) तंत्र की पूरक होगी।
 - **APA की अवधि अधिकतम 09 वर्ष हो सकती है (यदि करदाता ने रोल रोलबैक तंत्र का विकल्प चुना है तो पाँच वर्ष संभावित और 04 वर्ष पूर्वव्यापी सहित)।**
 - यह प्रक्रिया व्यवसायों द्वारा प्रदान किये गए संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनश्चिति करती है।

- सांख्यिकीय डेटा और सारांश जानकारी प्रकाशित की जाती है, लेकिन नषिकर्षण वव्यवस्था वाली संस्थाओं या आवेदकों के नामों का खुलासा कयि बनिा ।
- **व्यवसायों के लयि APA का महत्त्व:**
 - यह अंतरराष्ट्रीय लेन-देन हेतु नकिटतम दूरी की कीमत नरिधारण करने के लयि कर नशुचितता (Tax Certainty) प्रदान करता है ।
 - द्वपिकषीय या बहुपकषीय APA के माध्यम से संभावणत दोहरे कराधान के जोखमि को कम करता है ।
 - स्थानांतरण मूल्य नरिधारण ऑडिट जोखमि को समाप्त करके और वववादों को हल करके अनुपालन लागत को कम करता है ।
 - आवश्यक दस्तावेजों को पहले से रकिर्रड रखने का बोझ कम हो जाता है ।
 - APA, व्यवसायों को उनके लेन-देन की कीमतों को अनुचित तरीके से नरिधारण करने या कर अधिकारियों द्वारा चुनौती दयि जाने के जोखमि को कम करेगा ।
 - APA व्यवसायों के लयि अपने कर जोखमि और योजना का प्रबंधन करने के लयि एक प्रभावी उपकरण हो सकता है ।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT):

- यह एक वैधानिक नकिया है, जसि केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधनियम, 1963 के तहत स्थापणत कयि गया है, यह ववतित मंत्रालय में राजस्व ववभाग का एक हसिा है ।
- CBDT भारत में प्रत्यक्ष करों की नीत और योजना के लयि आवश्यक इनपुट प्रदान करता है, साथ ही यह [आयकर](#) ववभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लयि भी ज़मिमेदार है ।

दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA):

- DTAA दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरणत एक कर संधि है । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कइिन देशों में करदाता एक ही आय पर दो बार कर लगाने से बच सकें ।
- DTAA उन मामलों में लागू होता है, जहाँ करदाता एक देश में रहता है और दूसरे देश में आय अर्जणत करता है ।
- DTAA या तो आय के सभी स्रोतों को कवर करने के लयि व्यापक हो सकते हैं या कुछ कषेत्रों तक सीमणत हो सकते हैं जैसे शपणग, हवाई परवहन, वरिासत आदि से आय पर कर लगाना ।
- **वर्ष 1983 में भारत और मॉरीशस दोहरे कराधान को रोकने के लयि DTAA पर सहमत हुए ।** DTAA दोनों देशों के नविसयियों पर लागू होता है ।

भारत और मॉरीशस DTAA संशोधन में कया शामिल है?

- **मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT):**
 - संशोधणत प्रोटोकॉल भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में **मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT)** पेश करता है ।
 - यद उन लाभों को प्राप्त करना कसिी लेन-देन या व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य हो तो PPT समझौता लाभों से इनकार करता है ।
- **अनुच्छेद 27B:**
 - समझौते में एक नया अनुच्छेद 27B शामिल कयि गया है, जो 'लाभ की पात्रता' (Entitlement to Benefits) को परभाषणत करता है ।
 - यह अनुच्छेद उन शर्तों को नरिदषणत करता है, जणके तहत समझौते के लाभ, जैसे कबियाज, रॉयल्टी और लाभांश पर प्रतधारण कर (Withholding Tax) को कम करने से इनकार कयि जाता है ।
- **समझौते के दुरुपयोग को रोकने पर ध्यान देना:**
 - संशोधन का उद्देश्य DTAA के दुरुपयोग के माध्यम से **कर चोरी और बचाव** से संबंधणत चणताओं को दूर करना है ।
 - PPT को शामिल करके, संशोधणत समझौता यह सुनशुचणत करता है ककरि लाभों का अनुचित उद्देश्यों के लयि दुरुपयोग न कयि जाए ।
- **वणणत नविसयों के संबंध में अनशुचणतता:**
 - संशोधन के बावजूद DTAA के वणणत प्रावधानों के तहत कयि गए पछिले नविसयों के संबंध में स्पष्टता का अभाव है ।
 - ववतित मंत्रालय ने अभी तक मौजूदा नविसयों पर नए प्रावधानों के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जारी नहीं कयि है ।

भारत तथा मॉरीशस के बीच वाणज्यिक संबंध:

- **वर्ष 2005 से भारत, मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है ।**
- ववततीय वर्ष 2022-2023 के लयि मॉरीशस को भारतीय नरियात 462.69 मलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबक भारत को मॉरीशस का नरियात 91.50 मलियन अमेरिकी डॉलर का था, जसिमें कुल व्यापार 554.19 मलियन अमेरिकी डॉलर का था ।
 - भारत एवं मॉरीशस के बीच व्यापार में **पछिले 17 वर्षों में 132% तक की वृद्धि हुई है ।**
- वर्ष 2019 के मध्य तक **पेट्रोलियम उत्पाद, भारत से मॉरीशस को नरियात** की गई मुख्य वस्तु थी । मॉरीशस को अन्य भारतीय नरियातों में फार्मास्यूटिकल्स, अनाज, कपास, झींगा एवं गोजातीय मांस आदि शामिल थे ।
- मॉरीशस से भारत में नरियात की मुख्य मदों में वेनला, चकणतिसा उपकरण, सुइयाँ, एलयुमीनयम मशिरधातु, स्करैप पेपर, परषिकृत ताँबा एवं पुरुषों हेतु सूती वस्त्र शामिल हैं ।

- वर्ष 2000 से 2022 के बीच मॉरीशस से भारत में 161 बलियिन अमेरिकी डॉलर का संचयी FDI प्राप्त हुआ, जो मुख्य रूप से DTAA के कारण था।
- मॉरीशस और भारत ने 2021 में **व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (CECPA)** पर हस्ताक्षर किये।
 - CECPA किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है।
- वर्ष 2024 में मॉरीशस में **यूनफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एवं RuPay कार्ड सेवाएँ** भी लॉन्च की गईं।
 - मॉरीशस एवं भारत में उपयोगकर्ताओं को RuPay तथा UPI को अपनाने से घरेलू के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन करने में सुविधा प्राप्त होगी।

?????? ???? ???? ????:

??????. ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने तथा वदेशी निवेश को आकर्षित करने के भारत के परयासों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा APA हस्ताक्षरों में वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।

??????. कर चोरी को रोकने तथा भारत एवं मॉरीशस के बीच नष्टिपक्ष करधान प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु किये गए संशोधन के उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????/?/?/?/?/?/?/?/?

प्रश्न. अप्रवासी सत्त्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन वजिज़ापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के नरिणय के संदर्भ में नमिन्लखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2018)

1. यह आय कर अधनियिम के भाग के रूप में लागू कयिा गया है।
2. भारत में वजिज़ापन सेवाएँ देने वाले अप्रवासी सत्त्व अपने गृह देश में "दोहरे करधान से बचाव समझौते" के अंतरगत टैक्स क्रेडिटि का दावा कर सकते हैं।

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)